# ( यश मालवीय की कविता )

## मतदाता

आओ भाई रामसुभग
दरी बिछाओ रामसभग
मंच लगाओ राम सुभग
माइक लगाओ रामसुभग
नाचो गाओ रामसुभग
उनका क्या, भाषण देंगे
शब्दों के राशन देंगे
बहुत हुआ तो जनता को
भरे पेट अनशन देंगे
प्यासे भूखे भारत को
केवल जन गण मन देंगे
भींचो फ़िर खाली मुट्ठी
दर्द चबाओ रामसुभग
पीछे जाओ रामसुभग
मत खिसियाओ रामसुभग
देखो कितने नारे हैं
उन्हें पचाओ रामसुभग
वो सवार तुम मोटर हो
चौराहे का पोस्टर हो
वो हैं लाखों में तुम तो
दो कौड़ी के वोटर हो
उनकी है दुनिया सारी
तुम अपना ही कोटर हो
घड़ी–घड़ी पर मीटिंग है
चाय बनाओ रामसुभग
थाल सजाओ रामसुभग
गाल बजाओ रामसुभग
छप्पन भोग उन्हें सारा
तुम गम खाओ रामसुभग
शोर भरे सन्नाटे हैं
तेज हवा के चाटे हैं
सूखी–सूखी आंखें हैं
गीले–गीले आटे हैं
मन्दिर मस्जिद के लफ़ड़े
अधिनायक ने बांटे हैं
वो जुलूस से लौटे हैं
हाथ मिलाओ रामसुभग
आंख चुराओ रामसुभग
अजब समय है खुद को ही
सिर्फ़ डराओ रामसुभग
क्या गुजरात, अयोध्या क्या
बात–बात पर चर्चा क्या
पूरा घर ही खाक हुआ
अब हाथों का पर्चा क्या
पूछ रहीं खाली जेबें
गुजर बसर क्या, खर्चा क्या?
खुद को थोथे सपनों से
मत भरमाओ रामसुभग
क्यों शरमाओ रामसुभग
अब गरमाओ रामसुभग
मन में सोयी सोयी सी
आग जगाओ रामसुभग
उनसे अपना हक मांगो
जो कुछ है, बेशक मांगो
अपना जीवन, अपना है
क्यों झूठे नाटक मांगो
अपना आंगन चौका सब
लोटा थाली तक मांगो
तरह तरह के चक्कर हैं
मत चकराओ रामसुभग
क्यों कतराओ रामसुभग
अब टकराओ रामसुभग
उनकी ही औकात उन्हें
यूं बतलाओ रामसुभग

## पेज 1 का शेष

## फ़िर जीते नेता, जनता कब जीतेगी

पर क्या दुनिया में पहले जन के मतलब की राजनीतिक प्रणालियां नहीं रही हैं? क्या 'आप' पार्टी ने उन प्रणालियों का अध्ययन कर अपनी नीतियां व कार्यक्रम बनाये हैं? दूसरे शब्दों में, क्या 'व्यवस्था परिवर्तन' का उनका दावा महज़ जोश-भरा नारा है या एक सुविचारित आयोजन? इस आयोजन की रूपरेखा उनके दावों में कहां है?

जनता से रोज़गार, महंगाई से मुक्ति, बिजली-पानी-आवास-चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधायें, सुरक्षा-विशेषकर महिला सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, लोकतान्त्रिक भागीदारी, जैसे दावे तमाम पार्टियों ने इस चुनावी दौर में भी किये। यहां भी सबसे विश्वसनीय 'आप' पार्टी ही लगी। पर जनता के मतलब की बात यह होगी कि चुनावों के बाद इन दावों का क्या होगा? इन दावों को कितना और कैसे ज़मीन पर उतारा जायेगा?

जनता के लिये चुनाव शुरू हो चुके हैं। वह फ़िर ठगी जायेगी या उसे कुछ मिलेगा यह वक्त ही बतायेग। राजनीतिकों और उनकी पार्टियों को जो मिलना था वह मिल चुका हैं। उनके लिये चुनाव समाप्त हो चुके हैं। तो भी इन चुनावों ने यह तो दिखा ही दिया है कि क्यों कोई मोदी या गांधी परिवार जनता को अपनी जेब में रखकर नहीं घूम सकता।

## 22,000 करोड़ डकारनेवाला कार्पोरेट सुब्रत सहारा ले रहा मज़ा

यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट में ब्याज सहित 11 करोड़ देने के करार के बाद भी राजपाल ने रकम चुकाने की ओर कोई कदम नहीं उठाया। कई मौकों पर अदालत ने उसका व उसके वकील का झूठ पकड़ा भी और उन्हें चेतावनियां दीं। आखिर, तंग आकर, अदालत को उसे 10 दिन के लिये अदालती अवमानना में जेल भेजने का आदेश देना पड़ा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ठीक ही किया। राजपाल के आचरण और उसकी नीयत दोनों ही सरेआम अदालती कार्यवाही में बाधा पहुंचने वाले थे। यदि इसी मापदंड से सुब्रत सहारा के आचरण और नीयत को देखा जाय तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी गंभीरतम अवमानना के लिये उसे 42000 दिनों के लिये तिहाड़ भेज देना चाहिये। राजपाल का मामला 5 करोड़ और सुब्रत राय का 22000 करोड़; अनुपातिक न्याय में इतनी ही सज़ा बनेगी।

सुब्रत सहारा की जालसाज़ी एकदम साफ़ है। यह 22000 करोड़ की काली रकम को सफ़ेद करने की ऐसी दास्तान है जिसकी मिसाल हिन्दुस्तान तो क्या सारी दुनिया में कम ही मिलती है। यह दिखाया गया कि उक्त रकम शेयरों एवं अन्य प्रतिभूतियों की निवेशकों द्वारा खरीद-फ़रोख्त का नतीजा है। जब सेबी ने इस मामले की खोजबीन की तो पाया कि 'निवेशकों' के सारे नाम व पते फ़र्जी हैं। जाहिर है जालसाज़ी में कम्पनी के तमाम डायरेक्टर व उनके ऑडिटर इत्यादि भी गहरे लिप्त हैं।

मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुब्रत एकदम उछलकर बेहद ऊंची नैतिक ज़मीन पर जा बैठा। दर्जनों पेशियों में उसने किसी को अपने पर हाथ भी रखने न दिया। उसका अंदाज सेबी को ही नहीं, सुप्रीमकोर्ट को भी ब्लैकमेल करने वाला रहा। उसके विज्ञापन सभी जांचकर्ताओं व उससे सवाल पूछने वालों को काली नीयत वाला बताते रहे। बमुश्किल, सुप्रीमकोर्ट यह आदेश पारित कर सका कि सहारा समूह 22000 करोड़ की अपनी परिसम्पत्तियां सेबी के हवाले करे क्योंकि 'निवेशकों' के अस्तित्व पर सुब्रत राय एंड कम्पनी कोई प्रकाश डालने में विफ़ल रहे थे।

यहां भी सुब्रत ने सेबी को ठेंगा दिखा दिया। उसने दो विवादित भू-सम्पत्तियों के काग़जात सेबी को सौंपे, इस दावे के साथ कि उनकी कीमत 22000 करोड़ है। यह प्रयोजित आंकलन भी सुब्रत की जालसाज़ी का एक और नमूना है। सेबी ने इन भू-सम्पत्तियों का आंकलन कराने पर पाया कि बाज़ार में इनका 200 करोड़ भी नहीं मिलेगा।

सेबी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीमकोर्ट को दे दी है इस तर्क के साथ कि सुब्रत को ही कहा जाय कि वह स्वयं इन भू-सम्पत्तियों को बेचकर 22000 करोड़ उसे दे दे। जाहिर है, सुब्रत के फ़रिश्ते भी यह नहीं कर पायेंगे और अगली पेशी पर वह पुन: किसी अन्य जालसाज़ी के साथ सुप्रीमकोर्ट में खड़ा मिलेगा।

क्या सुप्रीमकोर्ट को अपनी अवमानना नज़र नहीं आ रही? जबकि सुब्रत राय का सारा आचरण पग-पग पर न्याय के रास्ते में रुकावट डालने वाला रहा है। देखें, कब तक सुप्रीमकोर्ट सुब्रत के प्रति नर्मी दिखाती रहेगी? और क्यों? महज़ इसलिये कि वह एक महाकार्पोरेट है।

## खेल, खिलाड़ी, खेल भावना पर भारी पड़ता खेल-प्रशासक

अभय के उपरोक्त दोनों निर्वाचन अनियमितताओं के जीते-जागते नमूने माने गये। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने इन संघों को बार-बार नियम कायदे के अनुसार निर्वाचन की सलाह एवं चेतावनी दी। दोनों संघों को नियन्त्रित करनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इन्हें कई बार चेताया। यहां तक कि अब भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भागीदारी की इजाजत भी मुश्किल से ही मिल पा रही है। तमाम प्रभावित खिलाड़ी अनिश्चितता से घिरे हुए हैं जिसका असर उनके अभ्यास व परिणाम पर पड़ना स्वाभाविक है। पर इससे अभय को क्या? अगर वह इन खेल संघों की मलाई नहीं खा सकता तो भाड़ में गए खेल और भाड़ में जायें खिलाड़ी। भारत सरकार बेबस बैठी है। क्योंकि खेल संगठन इन संघों का नियमित चुनाव तो करा नहीं सकते, लिहाज़ा वे भी इनका निलम्बन कर चुप बैठे हैं। सवाल है इस चक्की में पिसते खिलाड़ी क्या करें?

आई ओ.सी (अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिती) के दबाव में शर्मशार भारतीय ओलम्पिक संघ के सदस्यों ने रविवार दिनांक 8 तारीख को अपने आम सभा के बैठक बुलाई। इसमें सर्वसम्मति से संघ के संविधान में संशोधन करके चौटाला व भानोट जैसे किसी भी आरोपी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गयी है। संघ सदस्यों के व्यापक दबाव में संशोधन का प्रभाव भी चौटाला से पेश कराकर भानोट से उसका समर्थन कराया गया। इसके चलते अब भारतीय खिलाड़ियों का अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने का रास्ता साफ़ हो जायेगा।

# निगम का सफेद हाथी पी गया 12 लाख का तेल

**करनाल ( म.मो. )** प्रवीण कुमार शहर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ एवं सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम द्वारा वर्ष 2011 में एक सफाई मशीन खरीदी गई थी। सफाई मशीन शहर में आने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने करनाल की जनता को विश्वास दिलाया था कि अब उन्हें जगह-जगह फैले कचरे से और सड़कों पर फैली मिट्टी व गंदगी से निजात मिल जाएगी। करनाल के वासी भी अपने आपको शहर में सफाई मशीन पाकर सौभाग्यशाली समझ रहे थे और उनको विश्वास हो गया था कि अब शहर साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट राजेश शर्मा द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरवासियों का यह विश्वास धरातल पर लगता नजर आ रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में 16 लाख रुपए की लागत से नगर निगम ने भारी खर्च कर यह मशीन खरीदी थी। जो दो वर्षों में 12 लाख रुपए का तेल पीकर और 3 लाख 80 हजार रुपए रख-रखाव पर खर्च करवाकर खुड्डे लाइन खड़ी है। नगर निगम ने इतनी भारी-भरकम राशि जोकि लोगों की खून-पसीने की कमाई थी को बर्बाद कर दिया। अक्सर अफसरों के आने जाने वाले रास्ते को साफ करने वाली यह मशीन पिछले काफी समय से खराब खड़ी है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी इससे बेपरवाह हैं। यह मशीन पता नहीं किन कारणों से खरदी गई थी क्योंकि शहर करनाल की सड़कें इस तरह की मशीन के लायक बनी ही नहीं थी, इसी वजह से यह मशीन बार-बार खराब होती रही ओर नगर निगम का पैसा बर्बाद होता रहा।

शहर की सफाई व्यवस्था लाचार

आरटी आई कर्यकर्ता एडवोकेट राजेश शर्मा का कहना है कि नगर निगम के तहत आने वाले क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जिधर देखो गंदगी के बड़े-बड़े ढेर नजर आते हैं। कूड़े की ठीक तरह से लिफ्टिंग नहीं होती। यहां तक कि 16 करोड़ रुपए की लागत से बना कचरा प्लांट भी पिछले काफी समय से बंद पड़ा है। जहां पर हजारों टन कचरा फैला पड़ा है और पिछले काफी महीनों से जल रहा है। जो कि वातावरण में प्रदूषण और जहर घोल रहा है। आसपास के गांव के लोगों का जीवन नर्क बन चुका है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी आंखे बंद करके सो रहा है। संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही आलम रहा तो शहर करनाल में एक दिन महामारी फैलने का अंदेशा है। प्रशासन को तुरंत इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट राजेश शर्मा ने कहा कि जब करनाल की सड़कें इस लायक थी नहीं कि इस तरह की मशीन खरीदी जाए, तो तकरीबन 35 लाख रुपए का जो खर्चा हुआ है और जब अब किसी काम का नहीं है। इस मशीन की खरीद क्यों की गई। इस विषय की विजीलैंस जांच होनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

# गैस धांधली के खिलाफ़ प्रदर्शन

**फ़रीदाबाद ( इंकलाबी )** मज़दूर केन्द्र द्वारा गैस एजेन्सियों द्वारा गैस कनेक्शन के मनमाने दाम वसूलने, मज़दूर को महंगे दामो पर सोलर लालटेन, दाल, चावल रोल आदि महंगे दामों पर खरीदने पर मजबूर करने जैसी गैरकानूनी कार्यवाही के खिलाफ़ ज़िला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय पर एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में आज़ाद नगर झुग्गी बस्ती के महंगे गैस कनेक्शन के लिये मजबूर किये जा रहे लोगों सहित दर्जनों मज़दूर व महिलायें शामिल थी। खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने इस संबंध में शिकायतों का उचित निपटारा करने का आश्वासन दिया तथा गैस एजेन्सियों द्वारा गैस कनेक्शन के बहाने की जा रही लूट पर अंकुश लगाने का आश्वासन दिया।